भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 668
(03 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

जलवायु संबंधी विप्लवकारी घटनाओं में वृद्धि

668. श्रीमती प्रतिमा मण्डल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वैश्विक स्तर पर बढ़ती जलवायु संबंधी विप्लवकारी घटनाओं के संदर्भ में ग्रामीण रोजगार एवं परिसंपत्ति सृजन को जलवायु-सहनीयता तथा अनुकूलन के साथ संरेखित करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) महंगाई, खाद्य असुरक्षा तथा जीवन-यापन की लागत के दबावों का ग्रामीण परिवारों पर असमान रूप से प्रभाव पड़ने के बावजूद, प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं पर वास्तविक व्यय में आई गिरावट का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कामलेश पासवान)

(क): विकसित भारत-रोजगार के लिए गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के तहत: वीबी-जी राम जी अधिनियम , 2025, जलवायु सहनीयता, अनुकूलन और खराब मौसम जोखिमों को कम करना वैधानिक ग्रामीण रोजगार और परिसंपत्ति निर्माण ढांचे का एक अभिन्न अंग है। इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं को प्रति वित्तीय वर्ष एक सौ पच्चीस दिनों की बढ़ी हुई वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी प्रदान करके विकास भारत @2047 के राष्ट्रीय विजन के साथ ग्रामीण विकास ढांचे को जोड़ना है , साथ ही साथ टिकाऊ और उत्पादक ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण करना हैं। यह अधिनियम विशेष रूप से राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप जल सुरक्षा , मूलभूत ग्रामीण बुनियादी ढांचे , आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचे और खराब मौसम की घटनाओं के असर को कम करने के लिए विशेष कार्यों पर विषयगत ध्यान केंद्रित करने का प्रावधान करता है।

यह अधिनियम विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से विकेंद्रीकृत और साक्ष्य-आधारित योजना को अनिवार्य करता है, जो ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर संघरित होते हैं और भू-स्थानिक और अभिसरण-आधारित आयोजना प्रणालियों के साथ एकीकृत होते हैं। इस आयोजना के ढांचे के भीतर, जलवायु सहनीयता और अनुकूलन को मुख्य प्राथमिकताओं के रूप में शामिल किया गया है। कार्यों की अनुमेय और प्राथमिकता श्रेणियों में जल संरक्षण , वाटरशेड विकास, भूजल पुनर्भरण, वनीकरण, स्रोत स्थिरता, बाढ़ और सूखे से बचाव के उपाय , और प्राकृतिक संसाधन संपत्तियों का पुनरुद्धार और सुदृढ़ीकरण शामिल हैं। अधिनियम की अनुसूची में "बेहद खराब मौसम की घटनाओं को कम करने और आपदा तैयारी से जुड़े कार्यों" से संबंधित विशेष कार्यों का एक विशिष्ट विषयगत क्षेत्र प्रदान किया गया है , जिसमें आपदा जोखिम में कमी , जलवायु सहनीयता और बाढ़, चक्रवात, तूफान, सूखा, भूस्खलन, जंगल की आग और अन्य खराब मौसम की घटनाओं से ग्रामीण समुदायों और संपत्तियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है।

इस श्रेणी के तहत किए जाने वाले कार्यों में चक्रवात शेल्टर , बाढ़ शेल्टर और बहुउद्देशीय आपदा-प्रतिरोधी संरचनाओं का निर्माण; डायवर्शन चैनल, तटबंध और अन्य आपदा-बचाव कार्य; बाढ़ प्रबंधन के लिए तालाबों और जल संरचनाओं को स्थिर करना ; आपदा के बाद ग्रामीण सड़कों और सामुदायिक संपत्तियों का पुनर्वास और पुनर्स्थापना ; विंडब्रेक और शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण ; और जंगल की आग प्रबंधन कार्य जैसे कि फायर ब्रेक और ईंधन बफर जोन शामिल हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य जलवायु-अनुकूल गांवों का निर्माण करना है जो खराब मौसम स्थितियों का सामना कर सकें।

इसके अलावा, यह अधिनियम प्राकृतिक आपदाओं और असाधारण परिस्थितियों के दौरान परिचालन छूट के लिए भी प्रावधान करता है, जिससे केंद्र सरकार को समय पर प्रतिक्रिया और बहाली सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित परिवारों को अनुमत कार्यों के अस्थायी विस्तार , शिथिल दस्तावेजीकरण मानदंडों और बढ़ी हुई मजदूरी रोजगार सहायता की अनुमति देने का अधिकार मिलता है। ये प्रावधान सामूहिक रूप से जलवायु राहत और अनुकूलन को अधिनियम के तहत योजना और कार्यों के एक अंतर्निहित वैधानिक घटक के रूप में स्थापित करते हैं।

यहां यह उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत भी, मंत्रालय ने विशेष रूप से खराब जलवायु की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता के संदर्भ में ग्रामीण रोजगार सृजन और टिकाऊ परिसंपत्ति निर्माण को जलवायु सहनीयता और अनुकूलन के साथ जोड़ने के लिए नीति, कार्यक्रम और परिचालन उपायों की एक श्रृंखला शुरू की थी।

जलवायु अनुकूलन और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के साथ जोड़ी गई श्रेणियों के तहत वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 (28.01.2026 की स्थिति के अनुसार) के दौरान किए गए श्रेणी-वार कार्य निम्नानुसार हैं:

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 (28 जनवरी 2026 तक) के दौरान जलवायु से संबंधित कार्यों की श्रेणियों का विवरण				
श्रेणी का नाम	पूर्ण		चल रहे	
	कार्यों की संख्या	व्यय (लाख में)	कार्यों की संख्या	व्यय (लाख में)
सूखा प्रतिरोधी (सामुदायिक वृक्षारोपण)	1,99,331	36,373.25	10,79,956	3,08,702.74
बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा	66,800	44,031.42	2,70,011	1,76,353.02
भूमि विकास	2,73,350	1,02,702.71	5,64,718	3,16,397.14
सूक्ष्म सिंचाई कार्य	2,07,010	1,61,120.87	6,66,951	6,31,302.70
पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोद्धार	43,589	43,910.32	1,66,362	2,75,208.14
जल संरक्षण और जल संचयन	2,25,746	1,61,028.02	7,46,640	8,02,179.74

(ख): वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 (28.01.2026 तक) के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं पर किए गए कुल व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	कुल व्यय (रु. करोड़ में)
2022-23	177101.53
2023-24	150065.06
2024-25	172209.64
2025-26 (28.01.2026 की स्थिति के अनुसार)	106070.46

इन योजनाओं के माध्यम से मंत्रालय जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ देश के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास में मदद कर रहा है:

i) महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से 100 दिनों के लिए गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करने के अलावा, बड़ी संख्या में टिकाऊ परिसंपत्तियां भी बनाई जा रही हैं। यह आर्थिक या जलवायु संकट की अवधि के दौरान एक सुरक्षा जाल के रूप में भी कार्य करता है।

i i) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जरूरतमंद ग्रामीण आबादी के लिए आवास बनाए जा रहे हैं।

i i i) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण बस्तियों को जोड़ने के लिए सड़कें निर्मित की जा रही हैं।

i v) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वरोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देता है।

v) दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कौशल विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीब परिवारों के आर्थिक परिवर्तन में सहायता करती है।

vi) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) वृद्धों , विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करता है।